

>

Title: Need to address the problem of drinking water and irrigation facilities in Bharatpur, Rajasthan.

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहती हूं कि मेरा भरतपुर जिला एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है जहां पर बरसात कम मात्रा में होती है परिणामस्वरूप किसानों की कृषि भूमि को जरूरत के हिसाब से सिंचाई का पानी नहीं मिल पाता है और लोगों को गर्भियों के मौसम में पेयजल प्राप्त करने में दिक्कत होती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में आवश्यक पानी की आपूर्ति हेतु 25 वर्ष पूर्व वर्ष 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था। इससे राजस्थान 41.86 प्रतिशत पानी राजस्थान को और भरतपुर को 15 प्रतिशत औसत 1281 क्यूसेक पानी मिलना था, जो नहीं मिल पा रहा है। गुड़गांव कैनाल का 70 प्रतिशत का हिस्सा हरियाणा से होकर जाता है और उसके बाद मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में प्रवेश करता है। मुझे सदन को बताते हुए खेद हो रहा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र को हमेशा कम पानी मिलता है। दूसरी ओर सात साल पूर्व वर्ष 2012 में केन्द्रीय जल आयोग को गुड़गांव कैनाल के लिए दूसरा फेज का प्रस्ताव भेजा था, जो सात सालों से अभी तक लंबित है। इस दूसरे फेज में मेरे क्षेत्र की सिंचाई में अभाव एवं सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र डींग, कम्हेर एवं भरतपुर के...(व्यवधान) महोदय, थोड़ा-सा और बचा है। वहां के 207 गांवों को लाभ पहुंचाना था। लेकिन अब तक दूसरे फेज की स्वीकृति नहीं मिलने से उक्त क्षेत्रों को सिंचाई का लाभ नहीं मिला था। दूसरे फेज पर हरियाणा सरकार ने आपत्ति लगाई है।...(व्यवधान)